

(घ) पूरे देश में जमाखोरी-विरोधी अभियान को लागू करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किये जाने का प्रस्ताव है।

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण प्रणाली विभाग) में राज्य मंत्री (श्री विनोद शर्मा): (क) प्रधानमंत्री समय-समय पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कुशल कार्यान्वयन और यह सुनिश्चित करने पर कि आपूर्ति उपभोक्ताओं तक बहुत बल देते हैं।

(ख) से (घ) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यान्वयन हेतु प्रचालनात्मक जिम्मेदारी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की है। राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी में लगे और आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के उपबंधों तथा उसके तहत जारी नियंत्रण आदेशों का अन्य प्रकार से उल्लंघन करने वाले बेईमान तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करने की शक्तियाँ प्रत्यायोजित की गई हैं।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यान्वयन और आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रवर्तन की राज्य सरकारों के साथ समय-समय पर समीक्षा की जाती है। केंद्रीय सरकार को ऐसी सूचना नहीं मिली है कि राज्य सरकारों आवश्यक वस्तु अधिनियम के क्रियान्वयन के संबंध में केंद्रीय सरकार की सलाह का अनुसरण नहीं कर रही है। राज्य सरकारों आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत की गई कार्रवाई की सूचना केंद्रीय सरकार को आवधिक रूप से दे रही है।

केंद्रीय सरकार के पास आवश्यक वस्तु अधिनियम के उपबंधों के प्रवर्तन हेतु अलग से कोई तंत्र नहीं है। राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभागों के अधिकारी और कर्मचारी आवश्यक वस्तु अधिनियम के उपबंधों और उसके तहत जारी नियंत्रण आदेशों को लागू करने के अपने कार्य के एक हिस्से के रूप में, निरीक्षण करते हैं और छापे मारते हैं। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को यह सलाह दी गई है कि जब कभी भी यह महसूस किया जाए कि बेईमान तत्वों द्वारा सट्टेबाजी के लिए की गई जमाखोरी के कारण किसी आवश्यक वस्तु की उपलब्धता और मूल्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है तो वे जमाखोरी के खिलाफ विशेष अभियान चलाएं।

केंद्रीय सरकार राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र

प्रशासनों को इस संबंध में पत्रों और बैठकों के माध्यम से समय-समय पर सलाह देती है।

Cost of elimination of child labour

689. SHRI KRISHAN LAL SHARMA: Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether it is a fact that according to Government's estimates the cost of elimination of child labour comes to Rs. 12,720 per child;

(b) whether it is also a fact that International Labour Organisation has estimated the cost of elimination of child labour at Rs. 1,390/-; and

(c) if so, the reasons for the difference?

THE MINISTER OF LABOUR (SHRI G. VENKAT SWAMY): (a) and (b) No, Sir.

(c) Does not arise in view of reply to (a) and (b) above.

News-item regarding rising prices of pulses

690. SHRI RAJUBHAI A. PARMAR: SHRIMATI VEENA VERMA: SHRI SUSHILKUMAR SAMBHAJIRAO SHINDE:

Will the Minister of CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the report in the 'Statesman' of 23rd August, 1995 captioned, "price soar-buyers sore" regarding sky-packing prices of pulses, in the main commercial markets and in retail markets in the country; and

(b) if so, the comparative prices of each type of pulses and dals in January, April and September, 1995?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION (DEPTT. OF CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION SYSTEM) (SHRI

VENOD SHARMA): (a) and (b) Yes, Sir. A statement showing the comparative wholesale and retail prices of different types of pulses for January, April and September, 1995 is given below.

**Statement**

*Month-end wholesale and Retail prices of Pulses at selected centres.*

(Rs. per Qtl)

Items/ Centre	Wholesale Prices		
	Jan. '95	April '95	Sept. '95
<b>GRAM</b>			
Delhi	1250	980	880
Bombay	1800	1225	1225
Calcutta	1350	1130	950
Madras	1420	1221	1107
<b>ARHAR</b>			
Delhi	1450	1750	2300
Bombay	1701	2075	2300
Calcutta	1350	2000	2350
Madras	2000	2530	2520
<b>MOONG</b>			
Delhi	1570	1570	1675
Bombay	1400	1500	1600
Calcutta	NR	NR	NR
<b>MASUR</b>			
Delhi	1500	1500	1600
Bombay	1500	1200	1600
Calcutta	1480	1400	1750
<b>URAD</b>			
Delhi	1870	2450	2150
Bombay	1850	1600	2100
Calcutta	NR	NR	2700
<b>GRAM</b>			
Delhi	15.00	13.00	14.00
Bombay	19.00	15.00	13.00
Calcutta	16.00	16.00	14.00
Madras	16.00	13.00	12.50
<b>ARHAR</b>			
Delhi	18.00	19.00	31.00
Bombay	18.00	23.00	28.00
Calcutta	19.00	21.00	27.00
Madras	22.00	28.00	28.00

(Rs. per Qtl)

Items/ Centre	Wholesale Prices		
	Jan.95	April,95	Sept.95
<b>MOONG</b>			
Delhi	22.00	24.00	23.00
Bombay	22.00	23.00	23.60
Calcutta	22.00	22.00	24.00
<b>MASUR</b>			
Delhi	19.00	19.00	20.00
Bombay	19.00	18.00	19.00
Calcutta	19.00	20.00	23.00
<b>URAD</b>			
Delhi	30.00	36.00	36.00
Bombay	30.00	38.00	32.00
Calcutta	23.00	24.00	27.00

**SOURCE:** (i) State Govts. Civil Supplies Departments.

(ii) Dts. of Economics & Statistics, Ministry of Agriculture.

NR: Note Reported.

**Financial Assistance to Super Bazar**

691. **SHRI GOPALSINH G. SOLANKI :** Will the Minister of CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION be pleased to state:

(a) whether it is a fact that optimum utilization of funds is not being made in the Super Bazar;

(b) if not, the amounts obtained as financial assistance in the Super Bazar during the last three years separately from all Government and public sources;

(c) the amount out of the above financial assistance received and left unutilised at the end of each of the above said years; and

(d) the percentage of the unutilised amounts for each year?

**THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION (DEPTT. OF**